फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 316 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 19 जून, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Greenland's Quiet Stand

Eske Brun's decision in 1940 was made under extreme uncertainty. With no orders, no communication, and a global war unfolding, he chose to act in Greenland's best interests

The Cost of Knowledge

Civilization in Giambattista Vico's Thought

तृणमूल का फंड ''फ्रीज़'' करने की प्रक्रिया शुरु?

पूर्व खेल मंत्री अरुप बिस्वास, जो तृणमूल के कोषाध्यक्ष होने का दावा करते हैं, ने एच.डी.एफ.सी. बैंक को पार्टी का फंड ''फ्रीज़'' करने का निर्देश दिया

- हालांकि, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि अरूप बिस्वास पार्टी के कोषाध्यक्ष नहीं हैं। पार्टी ने 5 जून को अरूप की जगह सुभाषीश चक्रवर्ती को पार्टी को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था।
- तृणमूल कांग्रेस के पास 2000 करोड़ रूपए का फंड है और भाजपा के बाद तृणमूल दूसरी पार्टी है, जिसे सर्वाधिक राजनैतिक चंदा मिलता रहा है।
- अरूप बिस्वास कई बार विवादों से घिरे हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था अन्तर्राष्ट्रीय फुटबॉलर लिओनल मैसी के कोलकाता आगमन का, उस समय बतौर खेल मंत्री बिस्वास ने बार-बार मैसी को गले लगाने की कोशिश की।
- मैसी के स्टाफ ने इसे सुरक्षा उल्लंघन बताकर कोलकाता पुलिस को शिकायत की थी और कोर्ट ने भी बिस्वास को फटकारा व कहा कि, क्या मैसी आपके बचपन का दोस्त था, जो आप बार-बार उसे गले लगा रहे थे।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। तृणमूल कांग्रेस के 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के विशाल पार्टी फंड पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक बॉन्ड्स के माध्यम से दूसरा सबसे अधिक आर्थिक योगदान प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर, पार्टी को भाजपा के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजनैतिक चंदा मिला था।

पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने पार्टी के बैंक को सभी फंड फ्रीज़ करने का निर्देश दिया है। बिस्वास ने स्वयं को पार्टी का कोषाध्यक्ष (ट्रेज़रर) बताया था।

हालांकि, पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि पूर्व खेल मंत्री कोषाध्यक्ष नहीं हैं। उनके अनुसार, 5 जून से सुभाषीश चक्रवर्ती पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। बिस्वास को पहले आधिकारिक रूप से कोषाध्यक्ष घोषित किया गया था।

तृणमूल पार्टी को दिन में कई अन्य झटकों का भी सामना करना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में विधानसभा में बागी टीएमसी नेता ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे दी। अदालत ने पार्टी के कालीघाट गुट द्वारा किए गए आधिकारिक नामांकन को स्वीकार नहीं किया।

पूर्व तृणमूल खेल मंत्री अरूप बिस्वास, जो पिछले साल कोलकाता में लियोनेल मेसी के दौरे से जुड़े एक अप्रिय विवाद में भी फंस गए थे, ने पार्टी फंड फ्रीज़ करने के लिए पत्र भेजा है। मेसी मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद से वे कई दिनों तक नज़र नहीं आए।

उन्हें मेसी कार्यक्रम में गड़बड़ी के संबंध में पुलिस के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया गया था। सतरूप घोष, जिन्होंने मेसी का कार्यक्रम आयोजित किया था, ने बताया कि अरुप बिस्वास कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे और बार-बार मेसी को गले लगा रहे थे।

मेसी की इवेंट टीम ने भी शिकायत की है कि अरूप बिस्वास की उपस्थिति और विशेष रूप से उनका बार-बार मेसी को गले लगाना विश्वविख्यात फुटबॉलर के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों का उल्लंघन था। इस संबंध में ई-मेल पुलिस के पास है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीट री-एग्ज़ाम, चार दिन में वायुसेना ने 200 उड़ानें भरी

नई दिल्ली, 18 जून। आगामी 21 जून को दोबारा होने वाली नीट-यूजी की परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और लीक-प्रूफ बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने देश की सेना को मैदान में उतार दिया है। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) पिछले तीन-चार दिनों से देशभर के 18 तय जोन्स में परीक्षा के प्रश्नपत्र पहुंचाने के काम में जुटी हुई है।

इस बेहद गोपनीय और बड़े मिशन की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जो अब लगभग पूरी होने वाली है। इसका उद्देश्य है कि सरकार इस बार परीक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती।

- परीक्षा प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम 13 जून से शुरु हुआ और अब पूरा होने को है।

संसद और सड़कों पर हुए भारी हंगामे के बाद, इस बार सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। प्रश्नपत्रों के सील बंद बक्से को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर और बड़े मालवाहक विमानों को काम पर लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन शुरू होने से लेकर अब तक वायुसेना के विमान करीब 200 चक्कर लगा चुके हैं। विमानों के जरिए प्रश्नपत्रों को पहले मुख्य केन्द्रों तक पहुंचाया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'रामगोपाल यादव के नेतृत्व में सपा के 25-26 सांसद भाजपा जॉइन करेंगे'

उत्तर प्रदेश के उप मु.मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सहयोगी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया

- यूपी के मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख राजभर ने दावा किया कि सपा नेता रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिख कर सपा के उन सांसदों और विधायकों के नाम बताए हैं, जो भाजपा जॉइन करने को तैयार हैं।
- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राजभर के दावे को सही ठहराया और कहा कि 25-26 सपा सांसद दलबदल को तैयार हैं और विधानसभा चुनाव से पहले वे सपा छोड़ देंगे।
- यूपी में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने तो यहाँ तक दावा किया कि सपा और कांग्रेस के दो दर्जन सांसद उनके संपर्क में हैं तथा वे अवसर ढूंढ रहे हैं, भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व से मिलने का।

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। आगामी कुछ महीनों में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, समाजवादी पार्टी में संभावित टूट और दलबदल का संकेत देने वाले एक साइ-ऑप (मनोवैज्ञानिक अभियान) की चर्चा भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच लंबे समय से चल रही है।

तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) जैसी पार्टियों में आंतरिक उथल-पुथल के बीच, भाजपा और उसके सहयोगी दल कथित तौर पर विपक्ष की कमजोरी की एक व्यापक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में दावा किया कि एक बड़ा विभाजन जल्द होने वाला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है, जिसमें पार्टी के उन सांसदों और विधायकों के नाम हैं, जो भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राजभर के बयान को दोहराते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के 25-26 सांसद चुनाव से पहले टूटकर अलग होने तथा दल-बदल के लिए तैयार हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद, जो राज्य मंत्री और भाजपा के सहयोगी भी हैं, ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लगभग दो दर्जन सांसद उनसे संपर्क में हैं और केन्द्रीय भाजपा नेतृत्व से जुड़ने के अवसर तलाश रहे है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इन दावों को राजनीतिक शोर बताते हुए खारिज कर दिया है। वहीं, शिवपाल यादव, एस.टी. हसन, अवधेश प्रसाद और सनातन पांडे जैसे अन्य पार्टी नेताओं ने अखिलेश के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई है और भाजपा पर भय फैलाने का आरोप लगाया है।

समाजवादी पार्टी में नेतृत्व को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिवसेना के सांसदों ने बड़े नाटकीय अंदाज़ से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने की घोषणा की

सभी 6 बागी सांसद अलग-अलग शहरों से चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए और वापस निकल गए, किसी को खबर तक नहीं होने दी।

- समूचे घटनाक्रम का टाइम टेबल बड़ा रोचक है। सभी सांसद एक-एक कर देर रात दिल्ली हवाई अड्डे उतरे जहाँ से उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।
- इस प्रकरण में एकनाथ शिंदे व उनके सांसद पुत्र श्रीकांत शिंदे काफी एक्टिव रहे, बागी सांसदों से पहले श्रीकांत शिंदे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मिले।
- बागी सांसदों ने कहा कि उन्हें एकनाथ शिंदे गुट के सदस्य के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने स्पीकर को प्रस्ताव दिया और आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। एक भारी राजनैतिक बदलाव की खबर है, जो शिवसेना (यूबीटी) में एक और बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बन सकती है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट से जुड़े छह सांसदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होने का फैसला किया है।

भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार, इन छह असंतुष्ट सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक पत्र भेजकर शिंदे गुट में शामिल होने की अपनी मंशा जताई है। यह पूरी राजनीतिक गतिविधि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडियों में 18.60 करोड़ रूपए की मंजूरी दी

जयपुर, 18 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के आधारभूत ढ ांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे मण्डी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे।

- सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, मेड़ता व दूदू में यार्ड व सड़कों का निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई इस स्वीकृति से कृषि उपज मण्डी समिति सोजत सिटी (पाली), पलसाना एवं श्रीमाधोपुर (सीकर), अनाज मण्डी (बीकानेर), मेड़ता सिटी (नागौर) तथा दूदू (जयपुर) में विभिन्न विकास कार्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या नेतन्याहू यूएस-ईरान शांति समझौते में सबसे बड़े ''लूज़र'' हैं?

यूएस-ईरान वॉर में हालांकि कोई विजेता नहीं है, पर शांति पैक्ट के बाद ''लूज़र'' के रूप में नेतन्याहू का नाम लिया जा रहा है

- नेतन्याहू, जो अक्टूबर में इज़रायल में चुनाव का सामना करेंगे, के लिए शांति समझौता कड़वी गोली निगलने जैसा है।
- गत तीन वर्ष से नेतन्याहू ईरान के साथ विवाद में उलझे हुए हैं, साथ ही गाज़ा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह परेशानी का कारण है। इतने लम्बे युद्ध के बाद हमास अब भी गाज़ा में हैं, हिज्बुल्लाह लेबनान में जमा हुआ है और ईरान में भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। इस डील से इज़रायल का एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।
- हालांकि, अमेरिका व इज़रायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया था, पर शांति समझौते की वार्ता से इज़रायल को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। ईरान संघर्ष का शांतिपूर्ण अंत एक अंतरिम शांति समझौते के साथ हुआ, जिस पर डॉनल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन ईरान अभी भी मौजूद है और दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों के एक महीने लंबे हमले को झेलने के बाद भी टिके रहने में सफल रहा है।

पिछले आकलन के अनुसार, इस युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं रहा। लेकिन इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह संघर्ष एक राजनीतिक असफलता और बड़ा झटका साबित हुआ है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या 'बीबी' (नेतन्याहू का निकनेम) इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े ''लूज़र'' हैं?

नेतन्याहू के लिए यह वास्तविकता स्वीकार करना कठिन हो सकता है, खासकर इस स्थिति में, जब उन्हें अक्टूबर में होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव का सामना करना है। पिछले तीन वर्षों में नेतन्याहू ने ईरान, गाज़ा में हमास और लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ संघर्षों में प्रवेश किया। उन्होंने एक ''नया मिडिल ईस्ट'' बनाने का वादा किया था। तीन साल बाद स्थिति यह है कि कुछ सैन्य सफलताओं के बावजूद, ये संघर्ष इज़रायल को कोई स्थायी जीत नहीं दिला सके।

इसके बजाय ''नया मिडिल ईस्ट'' कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है- हमास अभी भी गाज़ा के एक हिस्से पर नियंत्रण बनाए हुए है, हिज़्बुल्लाह लेबनान में अभी भी सक्रिय है, और ईरान की कमजोर होती सरकार अभी भी यथावत कायम है, नए सर्वोच्च नेता और अधिक शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) के साथ। इसके अलावा, जहाँ अमेरिका और इज़रायल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को वाई प्लस सुरक्षा दी

मुंबई, 18 जून। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने गुरुवार को शिवसेना यूबीटी के छह बागी सांसदों को वाय प्लस सुरक्षा दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही इन सभी सांसदों के घर पर 24 घंटे पुलिस रखने की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि आज सूबे के कई जिलों में इन सभी छह सांसदों के खिलाफ शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी की ओर से इन सभी छह सांसदों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

- राज्य के कई जिलों में इन 6 सांसदों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान की मांग ने ट्रंप के दावों को खोखला साबित किया

ईरान ने कहा है कि होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से ''टोल टैक्स'' वसूली वाजिब मांग है

- 108 दिन चली लड़ाई के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शांति समझौते के 14 सूत्रीय एमओयू पर साइन तो कर दिए, लेकिन 108 दिन चले इस युद्ध से ट्रंप को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली।
- युद्ध शुरु होते समय अमेरिका ने ईरान की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को नष्ट करने, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को कमज़ोर करने, तेहरान में सत्ता परिवर्तन करने और ईरान को कमज़ोर करने के कई लक्ष्य तय किए गए थे, लेकिन उसे किसी भी लक्ष्य को पाने में पूर्ण सफलता नहीं मिली।
- शांति वार्ता में परमाणु कार्यक्रम पर कोई वार्ता नहीं हुई है। भविष्य में वार्ता करने की सहमति अवश्य बनी है। इस जंग के बाद होर्मुज़ पर नियंत्रण करने का ईरान का लक्ष्य अवश्य पूरा होता लग रहा है।
- होर्मुज़ स्ट्रेट के इस्तेमाल पर टोल वसूली की बात कर ईरान ने इस मार्ग पर अपने अधिकार को मान्यता दिलवाने की कोशिश शुरु कर दी है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा किए जाने के कुछ ही घंटों बाद, तेहरान ने यह सख़्त संकेत दिया कि संघर्ष से जुड़ी राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

ट्रंप द्वारा बार-बार दिए गए इस आश्वासन के विपरीत कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य बिना किसी शुल्क के फिर से खोला जाएगा, ईरान ने घोषणा की कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले जहाजों को 60 दिन की वार्ता अवधि के बाद शुल्क देना होगा। इस घोषणा ने न केवल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक के भविष्य को लेकर नई अनिश्चितता पैदा कर दी है, बल्कि यह सवाल भी और गहरा कर दिया है कि ट्रंप का समझौता वास्तव में कूटनीतिक सफलता है या शांति के नाम पर किया गया रणनीतिक समझौता।

विवाद का केन्द्र होर्मुज़ जलडमरूमध्य है, जो एक संकरा समुद्री मार्ग है और जिसके माध्यम से, संघर्ष शुरू होने से पहले दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस गुजरती थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल द्वारा संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध ने होर्मुज़ को एक रणनीतिक ''चोक पॉइंट'' (अहम लेकिन सँकरे रास्ते) में बदलकर वैश्विक आर्थिक दबाव का केन्द्र बना दिया था।

ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन के बीच 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के बाद बोलते हुए ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने स्पष्ट कर दिया कि तेहरान, वॉशिंगटन से युद्ध के बाद की व्यवस्था को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है।

गालिबाफ ने ईरानी सरकारी मीडिया से कहा, ''होर्मुज़ जलडमरूमध्य युद्ध-पूर्व की स्थिति में वापस नहीं जाएगा। होर्मुज़ पर ईरान का संप्रभु अधिकार है और निश्चित रूप से हम अपनी सेवाओं के लिए फीस लेंगे।''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान में सिख दम्पत्ति की हत्या की भाजपा ने निंदा की

नई दिल्ली, 18 जून। पाकिस्तान सरकार की अल्पसंख्यकों और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा में विफलता की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी निंदा की है। मरदान के एक गुरुद्वारे में सिख दंपति, 70 साल के जगन्नाथ और उनकी पत्नी की हत्या की निंदा करते हुए भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि यह घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाती है।

- भाजपा ने सवाल उठाया कि क्या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना राज्य प्रायोजित आंतकवाद का हिस्सा है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)